RAPID FIRE करेंट अफेयर्स (14 दिसंबर, 2019)

भारत-मालदीव संयुक्त आयोग की बैठक

द्विपक्षीय सहयोग को और मज़बूत बनाने के लिये **भारत और मालदीव** के विदेश मंत्रियों के बीच 13 दिसंबर को नई दिल्ली में वार्ता हुई। दोनों देशों के संयुक्त आयोग की यह बैठक चार साल बाद हुई। इससे पहले दोनों देशों के संयुक्त आयोग की पाँच बैठकें हो चुकी हैं। विदेश मंत्री एस. जयशंकर और मालदीव के उनके समकक्ष अब्दुल्ला शाहिद के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग पर विस्तृत वार्ता हुई। मालदीव के विदेश मंत्री के साथ 31 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है, जिसमें कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारी हैं। दोनों देशों के बीच संयुक्त आयोग की वार्ता से सहयोग का दायरा और विस्तृत होगा। ध्यातव्य है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अपने खास और समुद्री इलाके के दोस्त मालदीव के विकास के लिये भारत वचनबद्ध है। अभी हाल ही में भारत-मालदीव की दोस्ती को बढ़ावा देते हुए नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिये दोनों देशों की प्रमुख विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया था। कई तरह के क्षेत्रों को कवर करने वाली प्रमुख विकास परियोजनाओं का संयुक्त उद्घाटन यह बताने के लिये पर्याप्त है कि भारत की **नेबरहुड फर्स्ट** और मालदीव सरकार की **इंडिया फर्स्ट** नीतियों ने सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मज़बूत किया है।

सोशल मीडिया पोर्नोग्राफी पर अंकुश के लिये समिति

राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने सोशल मीडिया पर पोर्नोग्राफी के बढ़ते प्रसार और इससे बच्चों तथा समाज पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की समस्या को लेकर उच्च सदन के सदस्यों की एक तदर्थ समिति गठित की है। यह समिति इस समस्या को दूर करने के उपाय सुझाएगी। इस विषय पर उच्च सदन के सदस्यों के औपचारिक समूह को ही तदर्थ समिति में तब्दील किया गया है। समूह के संयोजक कॉन्ग्रेस के राज्यसभा सदस्य **जयराम रमेश** को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। सोशल मीडिया पर पोर्नोग्राफी के बच्चों सहित समूचे समाज पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करने के लिये बनाए गई इस तदर्थ समिति में सपा की जया बच्चन, आप के संजय सिंह, बीजद के डा. अमर पटनायक, कॉन्ग्रेस के एम.वी. राजीव गौड़ा और अमी याज्ञिक, तृणमूल कॉन्ग्रेस की डोला सेन, जदयू की कहकशां परवीन, भाजपा के राजीव चंद्रशेखर, विनय पी सहस्त्रबुद्धे तथा रूपा गांगुली, द्रमुक के तिरुचि शिवा, राकांपा की वंदना चव्हाण एवं अन्नाद्रमुक की विजिला सत्यनाथ शामिल हैं। समिति को इस विषय के सभी पहलुओं पर विचार कर समस्या के समाधान के बारे में अपनी रिपोर्ट एक महीने के भीतर पेश करने को कहा गया है।

मल्टी सेल बॉक्स लोड क्लास 70 पुल

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मु ने राजौरी में हर मौसम के अनुकूल 72 मीटर लंबा मल्टी सेल बॉक्स लोड क्लास 70 पुल राष्ट्र को समर्पित किया। यह पुल द्राज नाला पर है और द्राज क्षेत्र को राजौरी ज़िले के अंतर्गत तहसील कोट्रान्का से जोड़ता है। इस पुल का निर्माण सीमा सड़क संगठन ने किया है। द्राज पुल सेना और साथ-ही-साथ राजौरी ज़िले के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिये महत्त्वपूर्ण है। यह पुल सेना और स्थानीय लोगों को सभी प्रकार की और त्वरित आवागमन की सुविधा प्रदान करेगा। यह पुल क्षेत्र में सड़क नेटवर्क को मज़बूती प्रदान करेगा। गौरतलब है कि आवागमन की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण होने के कारण मौजूदा सेतु को राष्ट्रीय राजमार्ग विनिर्देशों से युक्त उन्नत बनाना आवश्यक था। द्राज पुल अब भारी यातायात के आवागमन में बिना किसी अवरोध के हर मौसम में आवागमन की सुविधा प्रदान करेगा, क्योंकि यह लोड क्लास 70 के लिये डिज़ाइन किया गया है।

बोरिस जॉनसन

ब्रेक्ज़िट को लेकर हुए आकस्मिक चुनाव में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री **बोरिस जॉनसन** को बहुमत मिल गया है। 1980 के दशक में मार्गरेट थैचर के दौर के बाद **कंज़र्वेटिव पार्टी** की यह सबसे बड़ी जीत मानी जा रही है। हाउस ऑफ कॉमन्स की कुल 650 सीटों में से बोरिस जॉनसन की कंज़र्वेटिव पार्टी को 360 सीटों पर जीत मिली, जबकि जेरेमी कॉर्बिन के नेतृत्व वाली **लेबर पार्टी** को 203 सीटें मिलीं। ध्यातव्य है कि ब्रिटेन में तय समय के मुताबिक, मई 2022 में चुनाव होने थे, लेकिन ब्रेक्ज़िट पर गतिरोध के चलते करीब ढाई साल पहले चुनाव कराने पड़े। संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमंस में 650 सीटों के लिये भारतीय मूल समेत 3,322 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरे थे। इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड के सभी निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान हुआ। इस चुनाव में मतदान बैलट पेपर पर कराया गया ताकि किसी तरह की आशंका न रहे। वर्ष 2017 के पिछले चुनाव में कंज़र्वेटिव पार्टी को 318 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि लेबर पार्टी को 262 सीटें मिली थीं।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/rapid-fire-current-current-affairs-14-december-2019